इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 792
24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

ओडिशा में मूल्य संवर्धन तथा डाउनस्ट्रीम इस्पात उद्योग

792 **डा. सस्मित पात्राः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अथवा समर्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों, डाउनस्ट्रीम इस्पात पार्कों, इस्पात प्रसंस्करण क्लस्टरों तथा सहायक उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से किए गए निवेश, सृजित रोजगार तथा निर्मित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कच्चे माल के निर्यात के स्थान पर ओडिशा में मूल्य संवर्धन तथा डाउनस्ट्रीम विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में इस्पात मूल्य श्रृंखला में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्रों की स्थापना, डाउनस्ट्रीम उद्योग, निवेश, क्षमता विस्तार, रोजगार आदि से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात कंपनियों के प्रौद्योगिकीय-व्यावसायिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। ओडिशा की क्रूड स्टील क्षमता वित्त वर्ष 2021-22 में 24.5 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 43.3 मिलियन टन हो गई है। ओडिशा में 22 इस्पात इकाइयां हैं जो कोल्ड रोल्ड, गैल्वनाइजिंग, कलर कोटेड और पाइप एवं ट्यूब जैसे मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 14.7 मिलियन टन है।

सरकार ने ओडिशा सहित पूरे देश में निवेश, घरेलू मूल्यवर्धन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: (i) मूल्यवर्धित विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरूआत (ii) घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति को अधिसूचित करना, जो सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देती है, ।

*****